1983 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2072, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं । इस प्रश्न में उल्लिखित शिकायत विशेषतौर पर दरभंगा जिले से संबंधित थी । अतः राज्य सरकार द्वारा उस जिले के संदर्भ में इस मामले की जांच की गई थी । इस जांच से पता चला है कि किर्लोस्कर, ऊषा, इण्डिया, भारत आदि के पम्पसेटों की विभिन्न दरें दर्शायी गई थीं जिनकी सप्लाई को व्यवस्था विभिन्न बैंकों द्वारा की गई थी । इसके अलावा, पम्पसेट 4500 रुपए में भी उपलब्ध कराए जा सकते थे परन्तु बैंकों द्वारा ऐसे पम्पसेटों के लिए 5,500 रुपए से लेकर 6,500 रुपए की राशि का भुगतान किया गया था ।

इसके बाद, राज्य सरकार और बैंकिंग प्रभाग को सभी संबंधितों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था ।

बिहार राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग द्वारा मामले की जांच कराई है । इससे यह प्रतीत होता है कि बिहार सरकार के लघु सिचाई विभाग ने 1982-83 में सिंक ट्यूबवैलों की एक योजना शुरू की थी जिसमें दरभंगा जिले को 2500 ट्यूबवैलों का लक्ष्य आवंटित किया गया था । राज्य सरकार के अधिकारियों ने मदों के लिए दरें निर्धारित की थीं । बैंकों की लाभार्थियों से परामर्श करने और उपयुक्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी । बैंकों को लाभार्थियों से सीधे ही आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

बैंकिंग प्रभाग ने सूचित किया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंक बिहार के दरभंगा जिले में कार्य कर रहे थे । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इन सभी बैंकों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया को छोड़कर किसी भी बैंक ने इस विभाग के 6 मार्च, 1985 के पत्र में उल्लिखित टाइप के अग्रिमों में किन्हीं अनियमितताओं की सूचना नहीं दी है । इसके अलावा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दरभंगा जिले में बोरिंग उपकरणों की सप्लाई और पम्पसेटों की अग्रिम धनराशि में अनियमितताओं के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के छह अधिकारियों और कुछ बाहरी लोगों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किये हैं और ये मामले न्यायालयों के समक्ष सुनवाई के लिए लम्बित पड़े हैं ।

इसके अलावा, जुलाई, 1987 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया था कि बिहार के खगड़िया जिले में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की महेशखूंट शाखा में की गई मामलों की जांच से सिंचाई परियोजनाओं हेतु लघु किसानों के लिए आवधिक ऋण की योजना में अनियमितताओं का पता चला था । उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के दो अधिकारियों और कुछ प्राइवेट लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये है ।

Agitation by the employees of the Federal Bank Ltd.

2495. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what are the reasons for the agitation by the employees of the Federal Bank Ltd.; and

(b) what steps are being taken by the Central Government towards conciliation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The agitation by the employees of the Federal Bank Ltd. is mainly on the following demands:—

(i) Improvement in the Staff Housing Loan Scheme;

(ii) Posting of Head Clerks/Special Assistants in the bank;

(iii) Wages of sweepers;

(iv) Promotion policy;

(v) Posting of additional cashiers (in case of increased workload in any branches),

@Previously Unstarred Question 2051 transferred from the 15 March, 1988.

(vi) Promotion of sub-staff to clerical cadre; and

(vii) Postponement of increments to probationers.

In addition, demands have also been made for restoration of certain concessions such as halting allowance, uniforms to sub-staff, computer allowance, concession to employees relating to gold loan which are reported to have been withheld and withdrawal of disciplinary cases, etc.

(b) The Central Industrial Relations Machinery seized the matter under conciliation and discussions were held on 19th January, 1988, 20th January, 1988; 4th February; 1988; 5th February, 1988; 1st March; 1988 and 2nd March, 1988. Though an agreement could not be brought about, both the parties have requested that the conciliation proceedings should not be declared as failed as they prefer a negotiated settlement rather than a reference for adjudication. In view of this common desire, for a nagotiated settlement, further intervention will be made by the Central Industrial Relations Machinery at the appropriate time.

Implementation of Fifteen-Point Programme

2496. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Minorities Commission has made its 15 point recommendation to the Government regarding protection of minorities in the country;

(b) whether these recommendations were forwarded to State Govts. by the Central Government for implementation of these recommendations in their States; and

(c) if so, the reaction/reply of each State and progress made by each of the State Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Pressure on Gujarat State Fertilizer Company for its Ammonia plant

2497. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pressure has been exerted on the Gujarat State Fertilizer Company not to open the price bids for its ammonia plant; and

(b) if so the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) and (b) No, Sir; it is not a fact that any pressure has been exerted on M/s. Gujarat State Fertilizer Company not to open the price bids for its proposed ammonia plant.

ITDC publicity work through DAVP

2498. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the amount spent by the I.T.D.C. on account of publicity work through D.A.V.P. and Private Agencies during the period 1st January, 1985 and 31st December, 1987 yearwise;

(b) the names and addresses of Private Agencies engaged for the purpose and amount given to each of the agency during the same period;